सभापति महोदय : यह मेरे हाथ में नहीं है, दूसरों के हाथ में है । इससे पहले कि मैं श्री रामावतार शास्त्री को आध घंटे की चर्चा प्रारम्भ करने के लिए कहूं, श्रम मंत्री, श्री भागवत झा आजाद, कुछ घोषणा करेंगे ।

17.28 hrs.

STATEMENT RE : APPOINTMENT OF AN EMPLOYMENT COMMISSION

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR, EMPLOYMENT AND REHABILITATION (SHRI BHAGWAT JHA AZAD) : Sir, it may kindly be remembered that this House passed a resolution for the appointment of an Employment Commission. The Employment Commission would consist of the following :

CHAIRMAN : Mr. B. Bhagwati, MLA, Assam, who was a member of this House.

M.P's. : 1. Shri Jyotirmoy Basu, Member of Lok Sabha.

2. Shri M. Anandam, Member of Rajya Sabha.

ECONOMIST : Dr. Gautam Mathur of Osmania University.

EMPLOYMENT COMMISSIONER : Shri V. L. Gidwani.

NOMINEES OF CENTRAL MINISTRIES :

(i) Dr. Ashok Mitra, Chief Economic Adviser Department of Economic Affairs.

(ii) Shri K. Balachandran, Additional Secretary, Industrial Development.

(iii) Shri J. C. Mathur, Additional Secretary, Department of Agriculture.

NOMINEES OF THE STATE GOVERNMENTS :

(i) Government of West Bengal —Shri D. N. Banerjee, Special Officer and Ex-Officio Secretary, Home Department.

(ii) Government of Madhya Pradesh : Shri N. Sundaram, Development Commissioner.

MEMBER-SECRETARY : Shri N.S. Pandey.

The proposed terms of reference of the Committee of Experts on Unemployment are :

(i) To assess the extent of unemployment and underemployment in all its aspects, taking into account the recommendations made by the Committee of Experts on Unemployment Estimates set up by the Planning Commission under the Chairmanship of Prof. M. L. Dantwala.

(ii) To recommend the directions in which the programmes included in the Fourth Five-Year Plan could be n ade more employment-oriented in their implementation, with due regard to their timely execution, economy and productivity and to the requirements of rapid economic development.

(iii) To suggest suitable strategies for employment generation, both short-term, and long-term, including technical, financial and fiscal measures, in respect of different sectors of the economy, taking into account the mobility of labour and the openings for employment and self-employment in the tertiary sector as a result of implementation of the Plan programmes and various measures initiated by the Government for activating the economy.

(iv) To suggest specific programmes for promoting productive employment and self-employment of the educated unemployed in general and the unemployed technical personnel such as engineers, technicians, etc. in particular, and to suggest measures to rectify the imbalance between the out turn of educated and technical persons on the one hand and the available employment opportunities on the other.

(v) To suggest a suitable machinery at the Centre and State level for continuous appraisal of the changing employment and manpower

situation and assessment of long-term demand and supply.

श्री रवि राय (पुरी) : यह रिपोर्ट कब तक दे देंगे इस बारे में कुछ नहीं बताया। रिपोर्ट कब तक मिलेगी ?

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : जिस ढंग से अभी यह रिपोर्ट पेश की गई है उससे लगता है कि कुछ न कुछ दाल में काला है। हम जानते हैं कि यह केवल जनता की आंख में धूल झोंकने के लिए किया गया है। यह गवर्नमेंट अगर कुछ करना चाहती है प्रैक्टिकल तो उसके लिए यह बताना आवश्यक है कि किस टाइम तक यह रिपोर्ट आयेगी। जब तक यह नहीं बताया जाता तब तक यही समझा जायगा कि लोगों की आंखों में धूल डालने के लिए यह प्रयास किया गया है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (बलरामपुर) : स्पष्टीकरण आना है तो इकट्ठा ही आ जाय। मैं भी यह जानना चाहता हूं कि संसद सदस्य के नाते श्री ज्योतिर्मय बसु और राज्य सभा के श्री आनन्दन इस में शामिल किये गये हैं, लेकिन अगर लोक सभा भंग हो गई तो ज्योतिर्मय बसु इस के सदस्य रहेंगे या नही रहेंगे यह भी स्पष्ट कर दीजिए।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : ऐसे तो मैं जो कमीशन अप्वाइन्ट किया गया है उसका स्वागत करता हूँ। लेकिन एक बात मैं यह जानना चाहता हूँ कि हम लोगों ने जो बार-बार कहा था अनएम्प्लायमेंट डोल के सिलसिले में, बेकारी भत्ता देने के बारे में, उसका कोई मेंशन इसके टर्म्स आफ रेफरेंस में नहीं है। तो हमारी यह मांग है कि अनएम्प्लायमेंट डोल का रेफरेंस भी इसके टर्म्स आफ रेफरेंस में होना चाहिए।

जहां तक कमीशन का सवाल है, कमीशन का इतिहास आप देखें तो मालूम होगा कि कमीशन बैठता है, कमीशन लेटता है और फिर कमीशन सो जाता है। तो यही डर मुझे इसके साथ भी लगता है और इसीलिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि अनएम्प्लायमेंट डोल दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है इसके बारे में अगर परिस्थिति साफ हो जाय तो अच्छा है ताकि आज जो बेकार हैं उनके दिमाग में यह बात आए कि नौकरी मिले या न मिले कम से कम बेकारी का भत्ता उन्हें मिलेगा।

श्री भागवत झा आजाद : सभापति महोदय, यह बात तो स्पष्ट रूप से सदन में कह दी गई है कि जहां तक बेकारी भत्ता देने का प्रश्न है वर्तमान आर्थिक व्यवस्था में यह कतई संभव नहीं है। जहां तक कमीशन के बैठने लेटने और सोने का प्रश्न है मैं यह कहूं कि सरकार निश्चयात्मक रूप से पूरे अपने विचार के साथ यह चाहती है कि यह कमीशन जल्दी से जल्दी अपना कार्य प्रारंभ करे और इसकी रिपोर्ट जल्दी से जल्दी हमारे सामने आए। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूँ कि हम बिलकुल सिंसियर हैं कि जल्दी से जल्दी यह काम प्रारंभ हो और जल्दी इसकी रिपोर्ट मिले।

श्री राम सेवक यादव (बाराबंकी) : अध्यक्ष महोदय, जल्दी का मतलब क्या है ? अगर जल्द वाले मतलब को समय के साथ बाँध दें तो ज्यादा अच्छा हो क्योंकि यह बड़ा मिसलीडिंग है। इसको समय के साथ बांधे।

श्री झारखंडे राय (घोसी) : पंजाब सरकार ने अभी एलान किया है कि बेकार ग्रेजुएट्स को वह महंगाई भत्ता देगी। तो यह उन्होंने कैसे किया अगर उनके पास धनराशि नहीं है और फिर भारत सरकार जो अधिक धनराशि संपन्न है वह क्यों नहीं कर सकती ?

———

17.35 hrs.

HALF-AN-HOUR DISCUSSION RE : LATE RUNNING OF TRAINS

सभापति महोदय : यह आधे घंटे की चर्चा